



इन्सॉल्वेंसी रज़ॉल्यूशन मानदंडों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

आई.बी.आई. (Insolvency and Bankruptcy Board of India – IBBI) द्वारा कॉर्पोरेट दवालियापन समाधान प्रक्रिया (corporate insolvency resolution process) के नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमोटरों सहित आवेदकों को उनकी क्रेडिट पात्रता और वशिवसनीयता के संबंध में कठोर मानदंडों के दायरे में रखा गया है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु

- इन संशोधनों के तहत रज़ॉल्यूशन पेशेवरों और लेनदारों की समिति पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में पहले की अपेक्षा अधिक ज़िम्मेदारी भी डाली गई है।
- यह संशोधन इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि एक रज़ॉल्यूशन योजना (resolution plan) के अनुमोदन से पहले भाग के रूप में पूर्वोत्तर रिकॉर्ड, क्रेडिट योग्यता तथा प्रमोटरों सहित रज़ॉल्यूशन आवेदक (resolution applicant) की वशिवसनीयता को सीओसी (Committee of Creditors) के अधिकार के दायरे में रखा गया है।
- संशोधित नियमों के अनुसार रज़ॉल्यूशन पेशेवर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सीओसी को प्रस्तुत की गई रज़ॉल्यूशन योजना में रज़ॉल्यूशन आवेदकों की वशिवसनीयता का आकलन करने के लिये सभी पर्याप्त प्रासंगिक विवरणों को शामिल किया गया है।
- रज़ॉल्यूशन आवेदकों के संबंध में प्रदान किये जाने वाले विवरणों में रज़िर्व बैंक द्वारा जानबूझकर गबन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में जारी दशा-निर्देशों के अनुरूप दोषसिद्धि, अयोग्यता, आपराधिक कार्यवाही एवं वर्गीकरण तथा सेबी द्वारा लगाए जाने वाले विवरण अर्थात् रोक (debarment) से संबंधित विवरणों को भी शामिल किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त रज़ॉल्यूशन पेशेवरों को भी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत अधोमूल्य लेन-देन (undervalued transactions), जघन्य ऋण लेन-देन (extortionate credit transactions) और धोखाधड़ी वाले लेन-देन (fraudulent transactions) से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत शामिल सभी प्रकार के लेन-देनों के संबंध में विवरण जमा करना होगा।

उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि कॉर्पोरेट दवालियापन समाधान प्रक्रिया एक वशिवसनीय और व्यवहार्य संकल्प योजना के रूप में सफल साबित हो, आई.बी.आई. द्वारा आई.बी.आई. (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) रज़ॉल्यूशन प्रोसेस, 2016 (CIRP Regulations) में संशोधन किया गया है।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है?

- वगित वर्ष केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की दशा में कदम उठाते हुए एक नया दवालियापन संहिता संबंधी विधायक पारित किया था। यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाऊन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटिजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- किसी भी कंपनी या साझेदारी फर्म में वयावसायिक नुकसान के चलते कभी भी दवालिया होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि कोई आर्थिक इकाई दवालिया होती है तो इसका मतलब यह होता है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्तिय फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है।
- यदि हो कि बैंकरप्सी कोड के तहत दवालियापन प्रक्रियाओं को 180 दिनों के अंदर नपिटाने की व्यवस्था की गई है। यदि दवालियापन को सुलझाया नहीं जा सकता तो ऋणदाता (Creditors) का ऋण चुकाने के लिये उधारकर्त्ता (borrowers) की परसंपत्तियों को बेचा जा सकता है।
- हालाँकि, बैंकरप्सी कोड केवल एन.पी.ए. समस्या का ही समाधान ही नहीं करता है, बल्कि यह भारत के बेहद पुराने और अप्रचलित दवालियापन कानूनों में सुधार भी करता है।

